

संपादकीय

संविधान पर चर्चा के मायने

ੴ

लो कसभा में सर्विधान पर दो दिवसीय चर्चा का दृश्य पूरे देश ने देखा। लोकसभा में सर्विधान पर बहस के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का उत्तर सुनकर समझा में आ गया कि उन्होंने संघ की साखा में सर्विधान के बारे में जो कुछ पढ़ा-लिया उससे ज्यादा वे सर्विधान के बारे में जानते नहीं हैं। सर्विधान पर बहस के दौरान उठाये गए एक भी सवाल का उत्तर देने के बजाय वे अपने सिर पर सवार जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के भूत को बिदारते नजर आये। वे नहीं बता पाए कि उनके युग में सर्विधान कैसे मजबूत हो रहा है? वे प्रधानमंत्री के स्तर का भाषण देने में हमेसा की तरह विफल हुए, उन्होंने सर्विधान पर भाषण देते समय सर्विधान पर अपने गहन अध्ययन का प्रदर्शन करने के बजाय सिफारिशों को सब उद्घाटित किया जो संघ की शाखाओं में स्थाय सेवकों को पिछले 100 साल से दीक्षित किया जा रहा है। मोदी जी संघ के पचारक हैं ये हकीकत है लेकिन वे देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए उन्हें शाखाओं के ज्ञान से ज्यादा सिखने की जरूरत है। उन्हें देश को बताना चाहिए था कि पिछले दस साल में उनकी सरकार में सर्विधान की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये? सर्विधान संशोधनों को लेकर माननीय मोदी जी ने पिछली सरकारों के कामकाज को सर्विधान के साथ खिलवाड़ बताया, लेकिन जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने सर्विधान के साथ जो भी किया तो डंके की चोट किया। यानि वे परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि -वे करें तो केरबटर ढाला, हम करें तो रास लीला। सर्विधान के साथ किस पार्टी और सरकार ने खिलवाड़? किया ये पूरा देश जानता है। कांग्रेस ने आपातकाल लगाया थे सभी को पता है। मोदी जी कहते हैं कि आपातकाल का कलंक कांग्रेस के माथे से कभी मिट नहीं सकता, लेकिन वे भूल जाते हैं कि इसी देश की जनता ने, विपक्ष की खिचड़ी जनता सरकार के गिरने के बाद मशीन और मशीनरी के बिना हुए आम चुनाव में कांग्रेस को विजय श्री देकर इस कलंक को मिटाया था। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक उनके सिर से जवाहर लाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, राहुल गांधी का यहां तक की राहुल गांधी का भूत उत्तरने वाला नहीं है और जब तक ये भूत उनके सर पर सवार रहेंगे वे न चैन से काम कर पाएंगे और न सर्विधान के विधान को समझ पाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश को आश्वस्त नहीं कर पाए कि उनके लिए सर्विधान बड़ा है या मनुष्यता? वे ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि उन्हें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द से तकलीफ है या नहीं? वे ये भी नहीं बता पाए की सर्विधान को लेकर सावधारक जो सोचते थे, क्या वे उससे सहमत हैं या नहीं? मौजूदा सरकार ने पिछले एक दशक में सर्विधान की सेवा किस तरह से की है, देश और दुनिया जानती है। ऐसे में सोचना जरूरी है कि संसद में सर्विधान पर इस तरह की चर्चा की सार्थकता क्या है। क्यों कि पीएम को देश के सर्विधान की गरिमा, व्यापकता, प्रावधानों व आयामों का ज्ञान तो होना ही चाहिये।

राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मुद्रा

४

प्रियंका सौरभ

सं सद में पीयासीन अधिकारियों की भूमिका तटस्थला बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि संसदीय कार्यवाही निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से संचालित हो। हाल ही में, विषयक ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उठाया, जिसमें उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया गया। यह स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता के लिए प्रमुख नेतृत्व भूमिकाओं में निष्पक्षता बनाए रखने के महत्व को उजागर करती से ही होकर जाता है। सरकार को अब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर गंभीरता से विचार करते हुए ऊर्जा बचत के लिए जरूरी उपाय अपनाने पड़ेंगे। इस मायने में सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण विकल्प है। भारत में 31 मार्च 2023 तक स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 416,059 मेगावाट थी। जिसमें जीवाशम ईंधन से 237,269 मेगावाट अथवा 57 प्रतिशत तथा गैर-जीवाशम ईंधन से 178,790

ईंधन की जरूरत

प्रमोट भार्गव

भा

रत सरकार के उपक्रम परमाणु ऊर्जा

निगम ने मध्यप्रदेश में चार नए परमाणु

ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी है। जल्दी ही ये

संयंत्र निर्माच, देवास, सिवनी और शिवपुरी में लगेंगे।

सब कुछ सही रहा तो जल्दी ही इन परियोजनाओं पर

काम शुरू हो जाएगा। इन संयंत्रों के शुरू हो जाने पर

1200 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली पैदा होगी।

भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता पिछले 10 साल में

करीब दोगुनी हो चुकी है। 2031 तक इसके तीन

गुना होने की उम्मीद है। भारत की जिस तेजी से

आबादी और अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसके

प्रबंधन और सुचारा सुविधा के लिए शहरीकरण के

साथ ऊर्जा की उपलब्धता आवश्यक है। इसी

नजरिये से परमाणु ऊर्जा का उत्सर्जन बढ़ाने की दिशा

में तेजी से प्राप्ति हो रही है। विद्युत की कमी पूरी हो

और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी न हो, इसके

लिए परमाणु ऊर्जा उपयुक्त मानी जाती है। एक बार

यदि कोई परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो जाता है तो

लंबे समय तक ऊर्जा की आपूर्ति बनी रहती है। ताप

विद्युत परियोजनाओं में कोयला जलाया जाता है।

इस कारण बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषित होती है। जो

अनेक बीमारियों का कारण बनती है। ऐसा अनुमान

है कि दुनिया में एक साल में करीब 15 लाख मौतें

वायु प्रदूषण से होती हैं। अतएव जीवाश्म ईंधन से

बिजली पैदा करना मानव आबादी को बीमार बनाए

रखना है। जबकि परमाणु ऊर्जा से पैदा बिजली

कार्बन मुक्त होने के साथ सस्ती भी होती है। भारत में

कुल ऊर्जा के उत्पादन में 80 प्रतिशत बिजली के बजाए

जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला को ताप विद्युत घरों

में जलाने से प्राप्त होती है। हालांकि देष में पानी, सौर्य

और वायु ऊर्जा भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने लगी

है। जीवाश्म ईंधन के ये बड़े विकल्प बनकर सामने

आए हैं। लेकिन सौर्य और पवन ऊर्जा के उत्सर्जन में

मौसम की बड़ी भूमिका रहती है। अतएव तेज हवाएं

नहीं चलने पर पवन ऊर्जा का निर्माण धीमा पड़ जाता

है। इसी तरह बारिश और ठंडे के मौसम में सूरज का

ताप मंद हो जाने से सौर्य ऊर्जा का उत्पादन कम हो

जाता है। परमाणु ऊर्जा के लिए थोरियम की

उपलब्धता जरूरी है। ये अच्छी बात है कि भारत में

थोरियम केरल और बिहार में बड़ी मात्रा में उपलब्ध

है। थोरियम धातु को वायु में गरम करने पर इससे

चिंगारियां फूटती हैं, जो ऊर्जायुक्त होती हैं। भारत में

भविष्य के ईंधन के रूप में थोरियम को परमाणु ऊर्जा

में बदलने के उपायों पर काम तेजी से चल रहा है। देश

में फिलाहल 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 23 परमाणु

रिएक्टर चालू हैं। परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने की दृष्टि

से 2024-25 के आम बजट में लघु परमाणु संयंत्रों

के लिए सरकार ने बड़े बजट का प्रावधान किया है।

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में यह नया प्रयोग है। पहली बार

निजी कंपनियों को लघु परमाणु संयंत्र समूचे देश में

स्थापित करने का अवसर दिया गया है। साथ ही

है। संसदीय कार्यवाही की तटस्थता बनाए रखने में संसद के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका बहस में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि सभी सांसदों को, चाहे वे किसी भी पार्टी से सम्बद्ध हों, बहस में भाग लेने के समान अवसर दिए जाएँ। निर्णयों में निष्पक्षता-अध्यक्ष द्वारा किए गए निर्णय पक्षपातपूर्ण झुकाव के बजाय संसदीय प्रक्रियाओं पर आधारित होने चाहिए। अध्यक्ष को सरकार और विपक्ष के बीच संघर्षों में मध्यस्थता करनी चाहिए, शिशुनारा बनाए रखते हुए रचनात्मक संवाद के लिए जगह बनानी चाहिए। एक तटस्थ पीठासीन अधिकारी संसद की अखंडता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, लोकतांत्रिक बहस के लिए अनुकूल बातावरण को बढ़ावा देता है। यदि अध्यक्ष को तटस्थ माना जाता है, तो संसदीय प्रणाली में विश्वास मजबूत होता है, जिससे स्वस्थ लोकतांत्रिक चर्चाओं को बढ़ावा मिलता है, जैसा कि यू.के. जैसे परिपक्ष लोकतंत्रों में देखा जाता है। संसदीय संस्था की वैधता की रक्षा के लिए पीठासीन अधिकारी को हमेशा निष्पक्षता का प्रदर्शन करना चाहिए। यदि अध्यक्ष को पक्षपाती माना जाता है, तो इससे संसदीय कार्यवाही में विश्वास कम हो सकता है और विधायी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम हो सकता है। अध्यक्ष के कार्यों में पक्षपात की धारणा के परिणामस्वरूप जनता में यह धारणा बन सकती है कि संसद को एक पार्टी के हितों की सेवा के लिए हेरफेर किया जा रहा है। पक्षपातपूर्ण अध्यक्ष संसद के भीतर राजनीतिक विभाजन को बढ़ा सकता है, जिससे सरकार और विपक्ष के बीच संघर्ष बढ़ सकता है। ऐसे परिदृश्य में, सरकार और विपक्ष अध्यक्ष के निर्णयों को चुनौती देने के लिए चरम रणनीति का सहारा ले सकते हैं, जिससे संसद में अधिक शत्रुपूर्ण और कम उत्पादक बातावरण बन सकता है। अध्यक्ष में कथित पक्षपात संसद की संस्था को ही कमजोर करता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यदि अध्यक्ष पक्षपातपूर्ण है, तो संसद के भीतर जवाबदेही के तंत्र विफल हो सकते हैं, जिससे अनियोन्त्रित कार्यवाही शक्ति की अनुमति मिलती है। यदि अध्यक्ष को किसी एक राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करते हुए देखा जाता है, तो इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं के प्रति जनता का मोहब्बंग हो सकता है। पीठासीन अधिकारी की भूमिका के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करने से निर्णय लेने में निरंतरता और निष्पक्षता बनाए रखने में मदद मिलती है। यू.के. संसद में, अध्यक्ष एक औपचारिक आचार सहिता का पालन करता है जो तटस्थता सुनिश्चित करता है, पक्षपात पर चिंताओं को दूर करने और संसदीय कार्यवाही में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद करता है। पीठासीन अधिकारियों के लिए स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र शुरू करने से अधिक जवाबदेही सुनिश्चित हो सकती है और पक्षपातपूर्ण कार्यवाहियों के रोका जा सकता है। पीठासीन अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम उठें संसदीय कार्यवाही की जटिलताओं को निष्पक्ष रूप से सभालने के लिए आवश्यक कौशल से लैस कर सकते हैं। निष्पक्ष निर्णय लेने और संघर्ष समाधान पर कोंद्रित नेतृत्व प्रशिक्षण अध्यक्ष को तटस्थता बनाए रखते हुए राजनीतिक दबावों को बहातर ढंग से नेविगेट करने में मदद कर सकता है। संसदीय समितियों और चर्चाओं में द्विदलीय सहयोग को बढ़ावा देने से निष्पक्ष रूप से सभालने के लिए अधिक संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल सकता है। संसदीय समितियों के भीतर अंतर-दलीय संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित करने से मतभेदों को दूर करने में मदद मिल सकती है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सरकार और विपक्ष के बीच मध्यस्थता में अध्यक्ष तटस्थ रहें। संसदीय कार्यवाही की तटस्थता सुनिश्चित करने में संसद के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, अध्यक्ष के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना, द्विदलीय सहयोग को बढ़ावा देना और स्पष्ट दिशा-निर्देशों और लंबे कार्यकाल के माध्यम से निष्पक्ष नेतृत्व सुनिश्चित करना आवश्यक है। दरअसल, इसके जरिए विपक्ष कहीं न कहीं संसद के दोनों सदनों में आसन को एक संदेश देना चाह रहा है कि अगर आसन निष्पक्ष नहीं दिखता है।

ऊर्जा संरक्षण से होगी बिजली की जरूरतें पूरी नजारिया

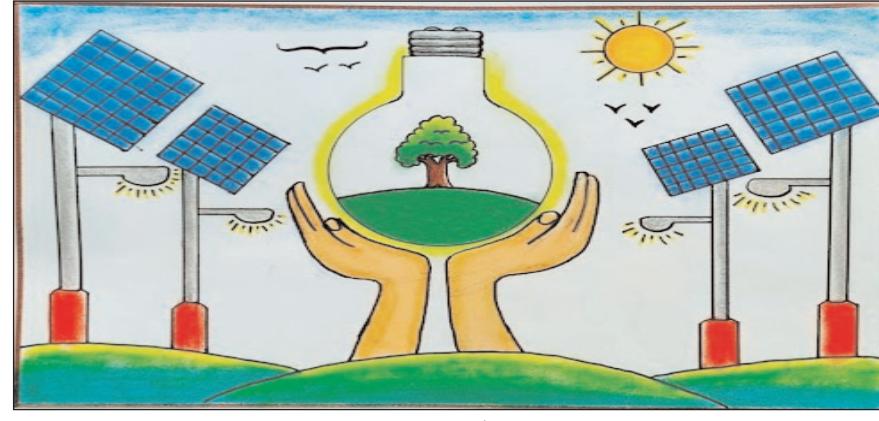
नज़ारिया

भारत में सौर ऊर्जा लगभग बाहर महिने उपलब्ध है। सौर ऊर्जा को और अधिक उन्नत करने के लिए हमें अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा के मामले में अधिक समय तक दूसरों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। ऊर्जा के क्षेत्र में हमें अपनी तकनीक और संसाधनों का उपयोग कर आत्मनिर्भरता हासिल करनी ही होगा। यह दुख का विषय है कि बहुत लम्बे समय तक हमने सौर ऊर्जा के उत्पादन व उपयोग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारे देश की परिस्थितियां विषम होने के कारण हमें सभी उपलब्ध ऊर्जा विकल्पों पर विचार करना होगा। इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण के व्यावहारिक कदमों को अपनाना होगा ताकि बड़े पैमाने पर बिजली की बचत हो सके। हमारे देश में ऊर्जा की मांग तीव्रता से बढ़ रही है। लेकिन उत्पादन में खपत की तुलना में बढ़ोतारी नहीं हो पा रही है। देश में चल रही पुरानी बिजली परियोजनाएं कभी पूरा उत्पादन नहीं कर पाई हैं। नई स्थापित

होने वाली परियोजनाओं के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं। देश में बिजली के इस संकट को अगर अभी समय रहते दूर नहीं किया गया तो आने वाले समय में गंभीर संकट का सामना करना होगा। दुर्भाग्यवश हमारे देश में खनिज, पेट्रोलियम, गैस, उत्तम गुणवत्ता के कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधन बहुत सीमित गात्रा में ही उपलब्ध हैं। ऊर्जा की बचत किये बिना हम विकसित राष्ट्र का सपना नहीं देख सकते हैं। आज जिस तेजी के साथ हम प्राकृतिक और पराम्परिक ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं। उस रपतार से 40 साल बाद हो सकता है हमारे पास तेल और पानी के बड़े भांडार खत्म हो जाए। उस स्थिति में हमें ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों यानि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे साधनों पर निर्भए होना पड़ेगा। लेकिन ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों को इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है और इस क्षेत्र में कार्य अभी प्रगति पर है।

रमेश सर्गफ धमोरा

ह मार जावन म प्रातोदान क बाब्धन काया व संचालन के लिए ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में बढ़द्दि के साथ-साथ प्रतिवर्ष ऊर्जा की मांग भी बढ़ती जा रही है। हम प्रतिदिन विभिन्न रूपों में ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अतः भविष्य में ऊर्जा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसका संरक्षण आवश्यक है। ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य विभिन्न उपयोगों के माध्यम से ऊर्जा का संरक्षण करना है। ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के माध्यम से ऊर्जा का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। जिससे वर्तमान की आवश्यता की पूर्ति के साथ भविष्य की जरूरतें भी पूरी हो सकें। ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग है। इसके अर्थ है ऊर्जा का अनावश्यक उपयोग ना करना एवं कम से कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए कार्य को करना। भारत एक ऐसा देश है जहां पूरे साल सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में साल भर में लगभग 310 दिनों तक तेज धूप खिली रहती है। भारत भाग्यशाली देश है जिसके पास सौर ऊर्जा के लिए खिली धूप की उपलब्धता, पर्यास मात्रा में भूमि की उपलब्धता, परमाणु ऊर्जा के लिए थेरियम का अथाह भंडार तथा पवन ऊर्जा के लिए लंबा समुद्री किनारा नैसर्गिक संसाधन के तौर पर उपलब्ध है। जरूरत है तो बस उचित प्रौद्योगिकी का विकास तथा संसाधनों का दोहन करने की।



मेगावाट अथवा 43 प्रतिशत शामिल। देश में कोयले से 205,235 मेगावाट अथवा 49.3 प्रतिशत, लिग्नाइट से 6620 मेगावाट, हाईड्रोपावर (पनबिजली) से 46,850 मेगावाट यानि कुल क्षमता का 11.3 प्रतिशत, प्राकृतिक गैस का योगदान 24,824 मेगावाट यानि क्षमता का महज 6 प्रतिशत और परमाणु ऊर्जा से 6780 मेगावाट, सौर ऊर्जा से 66,780 मेगावाट यानि 16.1 प्रतिशत, डीजल से 589 मेगावाट यानि 0.1 प्रतिशत, हवा से 42,633 मेगावाट यानि 10.2 प्रतिशत, बायो मास पावर/कोजेन से 10,248 मेगावाट, अपरिष्ठ से 554 मेगावाट, लघु हाइड्रो से 4944 मेगावाट, नाभिकीय से 6780 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। देश के सभी घरों तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए मौजूदा क्षमता कम पड़ेगी। इसके लिए वर्तमान क्षमता से कम से कम 30 फीसदी अधिक बिजली की जरूरत होगी। इसके लिये देश में पावर प्लांटों में 100 फीसदी बिजली उत्पादन करना होगा। बिजली आज पूरी दुनिया की सबसे अहम जरूरत बन गयी है। बिजली के बिना कोई भी देश तरकी नहीं कर सकता है। थे? से समय के लिये बिजली चली जाने पर हमारे अधिकतर काम रुक जाते हैं। बिजली हमारे जनजीवन का कब मुख्य हिस्सा बन गयी हमें पता ही नहीं चल पाया। आज हमारा पूरा जनजीवन बिजली से जुड़ा हुआ है। बिजली का उत्पादन मशीनों से किया जाता है। ऐसे मैं हमें हर बाल में बिजली का दुरुप्योग नहीं करना चाहिये।

बचत किये बिना हम विकसित राष्ट्र का सपना नहीं देख सकते हैं। आज जिस तेजी के साथ हम प्राकृतिक और पराम्परिक ऊर्जा के स्रोतों का उत्योग कर रहे हैं। उस रफ्तार से 40 साल बाद हो सकता है हमारे पास तेल और पानी के बड़े भंडार खत्म हो जाए। उस स्थिति में हमें ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों यानि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे साधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों को इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है और इस क्षेत्र में कार्य अभी प्राप्ति पर है। इन स्रोतों को इस्तेमाल में लाने के लिए कई तरह के वैज्ञानिक शोध चल रहे हैं जिनके परिणाम आने और आम जीवन में इस्तेमाल लाने के लायक बनाने में अभी समय लगेगा। इसे देखते हुए अगर हमने अभी से ऊर्जा के स्रोतों का संरक्षण करना शुरू नहीं किया तो आगे चलकर हालात बहुत बदतर हो सकते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि देश के अब सभी 5 लाख 97 हजार 464 गांवों का विद्युतीकरण हो गया है। सरकार की परिभाषा के मुताबिक वे गांव इलेक्ट्रिफाइड माने जाते हैं। जहां बेसिक इलेक्ट्रिकल इंफास्ट्रक्चर हो और गांव के 10 फीसदी मकानों और सार्वजनिक जगहों पर बिजली हो। भारत में बीते एक दशक के दौरान बढ़ती आबादी, आधुनिक सेवाओं तक पहुंच, विद्युतीकरण की दर तेज होने और सकल घेरेलू आय में वृद्धि की वजह से ऊर्जा की मांग काफी बड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मांग को सौर ऊर्जा के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकता है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपर संभावनाओं को देखते हुए अब विदेशी कंपनियों की निगाहें भी भारत पर हैं। आज विश्व का हर देश कागजी स्तर पर तो ऊर्जा संरक्षण की बड़ी-बड़ी बातें करता है। लेकिन ऊर्जा की बर्बादी में सबसे आगे नजर आते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो यहां विश्व में पाएं जाने वाली ऊर्जा का बहुत कम प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है। लेकिन इसकी तुलना में हम इसको कहीं ज्यादा खर्चा करते हैं। हमारे देश में आज ऊर्जा बचत के उपायों को शीघ्रतापूर्वक और सख्ती से अमल में लाए जाने की जरूरत है। इसमें देश के हर नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए। हर संभव ऊर्जा बचत करें तथा औरें को भी इसका महत्व बताएं।

ਈਧਨ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ ਪਰਮਾਣੁ ਊਰਾ

भा रत सरकार के उपक्रम परमाणु ऊजनिगम ने मध्यप्रदेश में चार नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी है। जलदी ही ये संयंत्र नीमच, देवास, सिवनी और शिवपुरी में लगाए गए सब कुछ सही रहा तो जलदी ही इन परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। इन संयंत्रों के शुरू हो जाने पर 1200 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली पैदा होगी भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता पिछ्ले 10 साल में करीब दोगुनी हो चुकी है। 2031 तक इसके तीन गुना होने की उम्मीद है। भारत की जिस तेजी से आबादी और अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसके प्रबंधन और सुचारू सुविधा के लिए शहरीकरण के साथ ऊर्जा की उपलब्धता आवश्यक है। इसके नजरिये से परमाणु ऊर्जा का उत्सर्जन बढ़ाने की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है। विद्युत की कमी पूरी हो और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी न हो, इसके लिए परमाणु ऊर्जा उपयुक्त मानी जाती है। एक बायद कोई परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो जाता है तो लंबे समय तक ऊर्जा की आपूर्ति बनी रहती है। ताप विद्युत परियोजनाओं में कोयला जलाया जाता है इस कारण बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषित होती है। जो अनेक बीमारियों का कारण बनती है। ऐसा अनुमान है कि दुनिया में एक साल में करीब 15 लाख मौतें वायु प्रदूषण से होती हैं। अतएव जीवाशम ईंधन से बिजली पैदा करना मानव आबादी को बीमार बनाना रखना है। जबकि परमाणु ऊर्जा से पैदा बिजली के कार्बन मुक्त होने के साथ सस्ती भी होती है। भारत में कुल ऊर्जा के उत्पादन में 80 प्रतिशत बिजली के क्षेत्र जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला को ताप विद्युत घरों में जलाने से प्राप्त होती है। हालांकि देश में पानी, सौरयांत्रिक और वायु ऊर्जा भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने लगी है। जीवाश्म ईंधन के ये बड़े विकल्प बनकर सामने आए हैं। लेकिन सौर्य और पवन ऊर्जा के उत्सर्जन में मौसम की बड़ी भूमिका रहती है। अतएव तेज हवाएँ नहीं चलने पर पवन ऊर्जा का निर्माण धीमा पड़ जाता है। इसी तरह बायाशक और ठंडे के मौसम में सूरज के ताप मंदा हो जाने से सौर्य ऊर्जा का उत्पादन कम हो जाता है। परमाणु ऊर्जा के लिए थोरियम के उपलब्धता जरूरी है ये अच्छी बात है कि भारत में थोरियम के क्षेत्र और बिहार में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम धातु को वायु में गरम करने पर इससे चिंगारियां फूटती हैं, जो ऊर्जायुक्त होती हैं। भारत में भविष्य के ईंधन के रूप में थोरियम को परमाणु ऊर्जा में बदलने के उपर्योग पर काम तेजी से चल रहा है। देश में फिलहाल 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 23 परमाणु रिकॉर्ट चालू हैं। परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने की दृष्टिकोण से 2024-25 के आम बजट में लघु परमाणु संयंत्रों के लिए सरकार ने बड़े बजट का प्रावधान किया है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में यह नया प्रयोग है। फली बात निजी कंपनियों को लघु परमाणु संयंत्र समूचे देश में स्थापित करने का अवसर दिया गया है। साथ ही



मॉड्यूलर (प्रतिरूपक) रिएक्टर के आधुनिकीकरण के लिए शोध और विकास पर भी धनराशि खर्च की जाएगी। जिससे परमाणु ऊर्जा में नई प्रौद्योगिकी का विकास हो। इसे पीपीपी मॉडल पर क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देष में स्वच्छ एवं वैकल्पिक बिजली को बढ़ावा देना है। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य धरनि:शुल्क बिजली योजना के तहत छोटे पर जो सौर संयंत्र लगाए जा रहे हैं, इन पर भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट जारी रही। अभी तक इस योजना के लाभ के लिए 1.28 करोड़ परिवार पंजीयन करा चुके हैं और 14 लाख आवेदन विचाराधीन हैं। इस योजना से 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) ऊर्जा परमाणु संयंत्र माने जाते हैं। इनकी बिजली उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट प्रति इकाई है, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की बिजली उत्पादन क्षमता की तुलना में एक तिहाई है। ये संयंत्र न्यूनतम कार्बन बिजली का उत्पादन करते हैं। विकसित भारत के लिए ऊर्जा की उपलब्धता एक बड़ी जरूरत है। इसलिए सरकार सिर्फ पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर भी नहीं रहना चाहती है। इसीलिए सौर और पवन ऊर्जा पर सरकार पहले ही काफी कुछ कर चुकी है। अतएव अब फोकस परमाणु ऊर्जा पर है। क्योंकि इसमें संभावनाएं अधिक है। लेकिन परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सुरक्षा के सवाल आड़े आते रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा को सरकार संचरत है। ऊर्जा बदलाव के संबंध में एक नीतिगत उपाय किए जा रहे हैं। इनसे तय होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह से पारंपरिक ऊर्जा की जगह धीरे-धीरे अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत का महत्व बढ़ रहा है। इस नीतिगत उपाय के तहत रोजगार, विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का भी समाधान होगा। अतएव इसी परिप्रेक्ष्य में निकेल, कोबाल्ट, तांबा और लिथियम जैसी धातुओं के उत्पादों के आयात पर बुल्क क्रमबद्ध घटाया जा रहा है। इन उत्पादों का प्रयोग परमाणु और सौर ऊर्जा के साथ दूसरे ऊर्जा

पायों में भी होता है। आयात सस्ता होने से विद्युतीय भारत में करने में आसानी होगी। यही उत्तर ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा और अंतरिक्ष ऊर्जा में इस्तेमाल होने वाली 25 धातुओं पर आधारित ऊर्जा को पूरी तरह खत्म कर दिया है। हाल ही कुछ देशों ने ओटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र करने में सफलता मिली है। इसी का भारत कर रहा है। भारत में एक और अर्सें परमाणु बिजली परियोजनाओं में विद्युत न शुरू हो रहा है, वहीं निजी निवेश से ऊर्जा बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत जिले के तापी में 22,500 करोड़ रुपए की लागत से 700 मेगावाट बिजली उत्पादन के दो ऊर्जा संयंत्र 22 फरवरी 2024 को राष्ट्र को दिया है। ये देश के पहले स्वदेशी परमाणु ब्रैंड हैं। ये उत्तर सुख्खा सुविधाओं से युक्त हैं। तिवर्ष लगभग 10.4 अरब यूनिट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करेंगे। जो गुजरात में बिजली की साथ अन्य प्रांतों का भी बिजली देंगे। बृद्धि कार्बन उत्पर्जन की दिशा में आगे दृष्टि से मील का पथर साचित होगे। अब भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में नियन्यों से 26 अरब डॉलर का निवेश किया है। यह पहल ऐसे स्रोतों से बिजली मात्रा बढ़ाने की दिशा में उत्तापा गया कदम युमंडल में प्रदुशण और तापानाब बढ़ाने न-बड़ा ऑक्साइड का उत्पर्जन नहीं करते हल्ली बार है जब परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में जी कंपनियों से पूँजी निवेश की मांग कर किलहाल भारत में परमाणु ऊर्जा कुल उत्पादन की तुलना में महज दो प्रतिष्ठत भी दिय यह निवेश बढ़ता है तो 2030 तक आपित विद्युत उत्पादन क्षमता का 50 और जीवाशम दैर्घ्यन के उपयोग से प्राप्त लक्ष्य करने में सहायता मिलेगी।

विश्व हिन्दू परिषद कल, आज और कल

तनवीर जाफरी

लाहौबाद कभी न केवल काग्रेस बल्कि समाजवादी व आर एस एस व विश्व हिंदू परिषद के भी बरिष्ठ व राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का गढ़ हुआ करता था। नेहरू-गांधी परिवार की तो यह कर्मस्थली थी ही इसके अतिरिक्त पुरोत्तम दस टंडन, मदन मोहन मालवीय जैसी अनेक विभूतियाँ भी इसी शहर से सम्बद्ध रहीं। इसी तरह दक्षिणपंथी विचारधारा के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख रहे राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जु भैया का नाम भी इलाहाबाद से ही जुड़ा हुआ है। ऐसा ही एक नाम था जस्टिस शिव नाथ काटजू का जो कि 1980 के दशक में विहिप के अध्यक्ष भी चुने गये थे। जस्टिस काटजू ने अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के निर्माण के लिए शुरूआती अभियान चलाया था। और इसी दौरान उन्हें नजरबंद भी कर दिया गया था। चूँकि मेरी भी औपचारिक शिक्षा इलाहाबाद में ही हुई इसलिये उस दौर के अनेक विशिष्ट जनों के साथ संबंध रखने का भी सौभाग्य मिला। जस्टिस काटजू भी उन्हीं में एक थे जिनके पास अक्सर मेरा आना जाना रहता था। जस्टिस काटजू विहिप के अध्यक्ष तो जरूर थे परन्तु वे पूर्णतः धर्मनिर्णय थे। इस्लामी इतिहास का भी उन्हें जबरदस्त ज्ञान था। शिया -सुनी विवाद और करबला की घटना जैसे विषयों पर तो वे अक्सर मेरे साथ बातें किया करते और मेरा ज्ञान वर्धन किया करते थे। बात 1977-78 की है उस दौरान मैं इलाहाबाद के मुहल्ले दरियाबाद के इमामबाड़ा सलवात अली खान नामक एक ट्रस्ट से परालियरिक रूप से जुड़ा हुआ था। यहाँ अनेक धार्मिक आयोजन हुआ करते हैं। इन्हीं में एक चालीसवें का जुलूस (मुररम के चालीस दिन बाद) भी इसी इमामबाड़े से निकला जाता है। इसी जगह से निकलने वाले चालीसवें के जुलूस का प्रारंभिक संबोधन करने के लिये जब मैं जस्टिस काटजू से निवेदन किया तो वे खुशी खुशी तैयार हो गये। हालांकि उन्होंने अयोध्या में मंदिर के निर्माण के लिए शुरू हुये विहिप आंदोलन तथा दरियाबाद की घनी मुस्लिम आबादी को भी रेखांकित किया। परन्तु मेरे संपूर्ण सुरक्षा व शान्तिपूर्ण आयोजन के आधासन के बाद वे कार्यक्रम से पूर्व स्वयं अपनी एम्बेसेडर कार चलाकर बिल्कुल अकेले ही दरियाबाद पधारा। यहाँ दरियाबाद चौराहे पर मौजूद मेरे साथियों ने उनका स्वागत किया व पूरे सम्पान के साथ उन्हें इमामबाड़ा सलवात अली खान लेकर गये। यहाँ मौजूद समूह के बीच जस्टिस काटजू ने कर्बला की घटना का जिक्र करते हुये न केवल अपनी तरफ से बल्कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की हैसियत से विहिप की तरफ से भी हजरत इमाम हूसैन व कब्रबाला के शहीदों को बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की। शेरवानी, टोपी और चूर्ढीदार पैजामा जैसा परिधान प्रायः धारण करने वाले काटजू साहब सभी धर्मों का पूरा ज्ञान रखते थे तथा उन्हें सम्पान भी देते थे। वे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद सभी धर्मों में प्रस्तर मेल जोल व सद्द्वाव के पक्षधार थे। उन्हें उंडू आरबी फारसी का भी पूरा ज्ञान था। यह था उस दौर के विश्व हिंदू परिषद का वह चेहरा जिससे भारत का गैर हिंदू समाज कभी भयभीत नहीं होता था। उसके बाद जबसे गुजरात को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रयोगशाला कहा जाने लगा तब से इसी विश्व हिंदू परिषद ने खुलकर इस्लाम व अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी आक्रामकता दिखाना शुरू कर दी। इसी विश्व हिंदू परिषद में बजरंग दल नामक एक और संगठन तैयार हो गया जो समय समय पर आक्रामक होते नजर आया। आज पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल पर अनेक आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इसी विश्व हिंदू परिषद ने योजनाबद्ध तरीके से गुजरात से शुरू कर कोरोनाकाल के दौरान देश के कई राज्यों में मुस्लिम दुकानदारों के प्रति नफरत फैलाकर उनसे सब्जी फल व अन्य सामान खरीदने के लिये हिंदू समाज के लोगों को मना किया। सीधे शब्दों में मुस्लिमों का व्यवसायिक बाहिकार करने की कोशिश की गयी। इसी विहिप ने बेटी बच्चा औ बहूलाओं नामक एक अभियान भी चलाया जिसके अंतर्गत किसी हिंदू लड़की के मुस्लिम लड़के से प्रेम संबंध होने की स्थिति में उस रिश्ते में दखल देना तथा वह अतिर्धार्मिक सम्बन्ध परवान न चढ़ने देना है।

